हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 25 जून 2025, समय 1305 (5 मिनट))

आज संविधान हत्या दिवस है। यह दिन हमें उन घटनाओं की याद दिलाता है, जब 25 जून 1975 को संविधान का गला घोटकर देश पर आपातकाल थोप दिया गया था। यह आपातकाल से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन भी है।

1975 में, आज ही के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक अशांति के खतरे का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की थी। यह घोषणा बढ़ती राजनीतिक अशांति और न्यायिक घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में की गई थी जिसने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सत्तारूढ़ नेतृत्व की वैधता को हिला कर रख दिया था। कार्यपालिका को अत्यधिक शक्तियां प्राप्त हुईं और करीबन सब कुछ केंद्रीय नियंत्रण में ले लिया गया था। घोषणा के बाद, अभिव्यक्ति की आजादी जैसे संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित कर दिया गया। सभी समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी गई। यहां तक कि वैधानिक निगरानी संस्था, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया था। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आपातकाल देश के इतिहास का सबसे काला युग था जब लोकतंत्र का समर्थन करने वालों पर अत्याचार किए गए थे।

यह भारत के इतिहास का काला दौर था लाखों लोग ने इमरजेंसी का पूरी ताकत से विरोध किया। लोकतंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गईं कि आज भी मन सीहर उठता है। आपातकाल के दौरान जेल गए प्रख्यात पत्रकार राम बहादुर राय ने आकाशवाणी से बातचीत की और उस दौरान हुए अत्याचारों के बारे में बताया।

इमरजेंसी अनावश्यक थी लेकिन इमरजेंसी के जो 21 महीने हैं वो पूरे देश में आतंक, भय, अत्याचार और बेगुनाहों के साथ अन्याय। इसके गुजरे हजारों लोग जेल में गए, बहुत लोगों की मौत हुई।

आपातकाल के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों ने अदालतों को आपातकाल घोषित करने के राष्ट्रपति के फैसले पर सवाल उठाने से रोक दिया था और प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

गृह मंत्री अमित शाह ने आपातकाल के लिए कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की सुरक्षा नहीं बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाना था। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि देश ने यह लड़ाई इसलिए जीती क्योंकि यहां की जनता तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।

बाइट - अमित शाह (0:21सेकंड)

लाखों लोग जेल में रहकर, अपने परिवार का सब कुछ नष्ट करकर, कई लोगों के कैरियर समाप्त भी हो गए और वो लड़ाई ने भारत के अंदर लोकतंत्र को जीवित रखा और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर आज विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े हैं।

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल आज शाम फरीदाबाद में “आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष” नाम से आयोजित विशेष कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस मौके पर श्री मनोहर लाल युवाओं को लोकतंत्र की रक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधानिक मूल्यों के संरक्षण हेतु जागरूकता का संदेश देंगे। कार्यक्रम में वे आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए जेलों में यातनाएं सहने वाले सत्याग्रहियों से भी भेंट करेंगे और उन्हें सम्मानित किया जाएगा।

हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती आरती सिंह राव ने उत्तराखंड में आयोजित राष्ट्रीय खेल 2025 में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए नेटबॉल में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी श्री कर्ण को सम्मानित किया है। श्री कर्ण वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय में कार्यरत हैं। उन्हें उनकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। राज्य की खेल प्रतिभा में उनके योगदान की सराहना करते हुए मंत्री ने उन्हें प्रशंसा पत्र भेंट किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लैब टू लैंड दृष्टिकोण से प्रेरित विकसित कृषि संकल्प अभियान भारत की कृषि संरचना को जमीनी अनुभवों के आधार पर नए सिरे से परिभाषित करेगा। उन्होंने कल नई दिल्ली में आयोजित विकसित कृषि संकल्प अभियान की वृहद समीक्षा बैठक में भाग लेने के बाद कहा कि लैब टू लैंड दृष्टिकोण का यह अभियान किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ भारत को वैश्विक फूड बास्केट के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। श्री श्याम सिंह राणा ने केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के विजन को भी प्रेरणादायक और भविष्यदृष्टा करार दिया। उन्होंने जानकारी दी कि अब यह अभियान रबी सीजन से पहले भी चलाया जाएगा, जिससे हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा।